RAJYA SABHA

Monday, the 26th July, 1982[45 *Sravana,* 1904 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock. Mr.

Chairman in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

♦221. [The questioner (Shri Manubhai Patel) wa sabsent. For answre *vide* col infra]

Proposals for electoral reforms received from the Election Commission

♦222. SHRI LAKHAN SINGH: 1
SHRI LAL K. ADVANI:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the main features of each proposal for electoral reforms received from time to time from the Election Commission so far and the dates of receipt thereof;

(b) the action taken regarding each proposal: and

(c) when did Government first state in the House that the question of electoral reforms was under their consideration?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL): (a) Statements I to IV hereto annexed set out the main features of the proposals for electoral reforms received from time to time from the Election Commission so far.

(i) *Statement I* contains all the proposals received along with the Election Commission's letter dated the 22nd October, 1977, *[See* Appendix CXXIII Anne-xure No. 54]. It may however be mentioned that a good number of these proposals actually date back to 1970 and had been considered by the Joint Committee of the Houses of Parliament on amendments to election law which, was constituted in 1971. The proposals in Statement I had been laid on the Table of the House in connection with answer to Rajya Sabha Unstarred Question No. 44 dated the 9th June. 1980.

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Lakhan Singh.

(ii) *Statement 11* contains the main sugl gestions for electoral reforms made on the 26th September, 1980 by the then Chief Election Commissioner in his Address to the Voters Council and Citizens for Democracy, Delhi [See Appendix CXXIII, Annexure No. 55]. These suggestions have also been laid on the Table of the House in connection with answer to Rajya Sabha Unstarred Question No. 564 dated the 24th November, 1980.

(iii) *Statement III* is a copy of Chaptei-XVI of the Report of the Election Commission on the General Elections' to the House of the People and Legislative Assemblies 1979-80 and Vice-Presidential Election 1979—Volume I. *[See* Appendix CXXIII, Annexure No. 56]. This Chapter contains the main recommendations for electoral reforms made by the Commission in the said Report. It may also be mentioned that a copy of the said Report was laid on the Table of the House on the 22nd December, 1980.

(iv) *Statement IV* contains the recom-mendations which have been received from the Election Commission subsequent to the Report mentioned in (iii) above together with the dates on which the Commission made those recommendations. *[See* Appendix CXXIII. Annexure No. 57].

(b) Decisions have been taken in respect of only six of the proposals as mentioned in *Statement V* annexed. *[See App*-pendix CXXIII, Annexure No. 58]. The rest of the proposals have been under consideration as explained below:—

The proposals in Statement I were placed after due examination in the Ministry, before the then Cabinet which constituted a Committee to consider the same. The Committee, took decisions on a number of proposals and decided that in regard to the remaining proposals, the then Minister of Law, Justice and Company Affairs might take the necessary decisions and place a comprehensive paper before the Cabinet. Before this could be done, the Sixth Lok Sabha was dissolved. After the formation of the present Government, the proposals mentioned in Statement I were re-examined and the new proposals received from the Election Commission were examined in detail in the Ministry and the matter was placed before the Cabinet in December, 1981. The Cabinet

referred the matter to a Committee and the various proposals are stiH under the examination of this Committee.

(c) After the receipt of the Commission's proposal in October, 1977 it was stated in an.wer to the Rajya Sabha Starred Question No, 24 dated the 14th November, 1977 on the Report of the Tarkundt- Committee and again in connection with Rajya. Sabha Starred Question No. 163 dated the 21st November, 1977 on electoral reforms that the proposals for amendments to election law were under examination/consideration.

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय महोदय, मंत्री जी ने समय-समय पर चुनाव आयोग की सिफारिशों का और प्रस्तावों का जिक्र किया है लेकिन यह नहीं बताया कि सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है और कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार लागू करने को तयार है इस सम्बन्ध में मंत्री जी प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने अपने जवाब में यह कहा है कि जितने प्रोपोजल्स समय-समय पर आई हैं उन प्रोपोजल्स पर मिनिस्ट्री आफ लॉ ने अपन राय कायम कर के केबिनट के पास मामला पहुंचाया और केबिनट ने आदेश दिया कि इन सारी प्रोपोजल्स को एक सब कमेटी एग्जामिन करे और इसके एग्जामिन करने के बाद फिर अपोजीशन पार्टीज के साथ बैठ कर जो टैंटेटिव निर्णय गवर्नमेन्ट ले वह डिसकस किये जाएं । अगर जरूरत हुई तो कुछ मामलों पर स्टेट्स से भी बातचीत करन पड़ेगी । तो यह कहना कि हमारा विचार क्या है मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि जब तक सब कमेटी फैसला न कर दे मेरे लिये यह कहना कि हमारा विचार फाइनल हो गया है बिलकुल मुश्किल है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो तारकुण्डे कमीशन की कुछ सिफारिशें हैं और इस समय जो लिखित उत्तर में मंत्री जी ने दी हैं तो तारकुण्डे कमीशन की सिफारिशें ऐसी कौन सी हैं जिस पर सरकार अपना कोई विचार रखती है या उस सम्बन्ध में कोई विशेष रूप से अपनी बात रखना चाहते हैं मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसका मंत्री जी स्पष्टीकरण दें ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जितनी प्रोपोजल्स थी उन सारी प्रोपोजल्स को देखने के बाद लॉ मिनिस्टर ने कुछ प्रोपोजल्स केबिनेट के सामने पेश की हैं उनमें से एक-एक प्रोपोजल को ऐग्जामिन कर के आपको बताने के लिए बहुत समय चाहिये लेकिन सब-कमेटी की बैठकें पहले भी हुई हैं और कल दोबारा हम करने जा रहे हैं । अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते क्योंकि सब कमेटी अपने डिसीजन लेने के बाद आप लोगों के सामने आना चाहती है । हमारी बैठक कल होने वाली है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, इस मामले में इस सदन में अनेक बार सवाल पूछे गये हैं और इस सदन की इतनी ही इच्छा है कि यह चुनाव सुधार जल्द से जल्दी हो लेकिन जितने उत्तर मिलते हैं, उदाहरणत: आज यह जो पोथना दिया है विधि मंत्री जी ने इस प्रकार का पोथना अनेक बार पहले दे चुके हैं। इलैक्शन कमीशन की रिकमेंडशन्स हैं, तारकुंडे कमेटी की रिकमंडेशन्स हैं । मैं पुराने रिकार्ड देखता हूं उनमें 24 नवम्बर 1980 को आज से लगभग 20 महीने पहले तत्कालीन विधि मंत्री श्री शिव शंकर जो इस समय बैठे हैं, उन्होंने कहा —

"All these proposals connected with electoral reform are comprehensive in nature. The decisions on them not only require careful consideration of the full import of implications but also discussions with political parties and al« with State Governments in certain cases."

पोलिटिकल पार्टीज से कोई डिसकशन नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेन्ट से कोई डिसकशन नहीं हुआ है और जो कमेटी इन्होंने बनाई है इसकी भी मीटिंग क्योंकि हमने सवाल पूछा है इसलिए कल उन्होंने निश्चित की है, मार्च 11, 1982 को अभी कुछ महीने पहले विधि मंत्री जी ने कहा :

"'The matter *is* now receiving attention at the highest level."

I presumed that the Prime Minister herself was considering the matter and veiy soon we would have the report from the Law Minister. Instead of that even today all that we have is that "the Sub-Committee is meeting tomorrow." Can a specific time limit be prescribed?

श्री सभापति : अब तो वक्त कम होते-होते 24 घंटे पर आ गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या इस साल में कम से कम जरूर यह काम पूरा कर देंगे ? इतना समय इलैक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस को हो गया है, पहले भी एक सब कमेटी ने फैसला कर के कुछ किया था उसको इम्पलीमेन्ट करने का तो आपको श्रेय मिलगा। मैं तो चाहता हूं कि कौशल जी इसका श्रेय लें इस महत्वपूर्ण काम को करें। एक दूसरी चीज जिसका उन्होंने जिक्र किया है – अपने उत्तर में वह है आइडेंटिटी कार्ड का।

Vou have referred *to* the Election Commission's recommendation about the identity cards and you have accepted it in principle. You have said that the scheme relating to introduction of photographed identity cards to voters in elections has been approved in principle. I would like to know from the Law Minister one specific question. Here in Delhi elections are due. I do not know when they will be held, but I can presume that they will be held immediately after the Asian Olympics are over in the month of January or February. Is it possible to implement this principle of photographed identity cards in Delhi to check impersonations which take place on a massive scale in Delhi? Is the Government willing to give an assurance to the House on that score?

श्री जगन्नाथ कौशल : जहां तक आडवाणी साहब यह आश्वासन चाहते हैं कि इस साल के अंदर-अंदर हम आपके सामने आयें, मैं यह आश्वासन देने के लिए तैयार हूं कि इस साल के अंदर-अंदर तो क्या उससे पहले हो ले आयेंगे और यह कहना कि...

डा० रफीक जकरिया : अब आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं रही।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पिछले साल यह भी कहने को तैयार नहीं थे।

श्री जगन्नाथ कौशल : यह कहना कि आपके कहने से आपके दबाव से, आपके प्रेशर से आपके परसुएंस से हम कल और एक मीटिंग करने जा रहे हैं, मैं हाउस के बेनीफिट के लिए कह रहा हूं कि मीटिंग पहले भी की थी यह दुबारा करने जा रहे हैं। कोशिश हमारी यह है कि हम जल्दी निर्णय लेकर आपके सामने आयें ताकि आपस बातचीत करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। बाकी जहां तक जो बात हमने इन प्रिंसीपुल मान ली है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : उनका एक सवाल यह भी था कि एशियाड के पहले होगा या बाद में या एशियाड में एक आइटम लगेगा ?

श्री जगन्नाथ कौशल : यह तो इनका अनुमान है कि इलेक्शन कब होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आइडेंटिफिकेशन कार्ड को इन प्रिंसीपुल इम्प्लीमेंट करेंगे यह मेरा सवाल है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : अगर यह पासिबुल होगा तो जरूर करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Last question. I do not think it requires much more time. Mr. Dhabe.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Sir, last time when we discussed this question, it was brought to thj notice of this House that elections to the Councils from the local bodies have not been held in some States for the last ten years or so because the local bodies have been superseded and elections. . .

MR. CHAIRMAN: But this is not about local bodies.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I am coming to that Elections to the Council are under the jurisdiction of the Election Commission. One of the major recommendations made in this report under item 19 is that such elections to local bodies should be brought within the jurisdiction of the Election Commission. Today the position is that in many States elections to the Councils from the local bodies are not held and therefore there are no representatives on the Councils from the local bodies for the last 10 years or so. May I know from the Minister whether he will take immediate steps to amend the law and bring it under the Election Commission and direct the States to hold elections to the local bodies like municipal bodies or corporations se> that Council elections from the local bodies could be held?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह मामला भी देखा जायेगा ।

श्री सभापति : कल होगा, अच्छा मिस्टर मट्टू साहब आप पूछ लीजिए ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: The Law Minister has said that 70 proposals are under the consideration of the Government with regard to the election reforms. I would request the Law Minister to let us know whether one of these is anti-defection law on the lines of the Jammu and Kashmir law and whether this is under consideration.

श्री जगन्नाथ कौशल : जी हां, वह भी है ।

MR. CHAIRMAN: Question No, 224. Question No. 223 is postponed.

*223. *Transferred to the 5th August* 1982]

कोयला खनन के लिए भूमि का अर्जन

*224. श्री राम नरेश कुशवाहा :†
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खनन हेतु पुरानी एवं नयी योजनाओं के विस्तार के लिए सी० सी० एल० बी०, सी० सी० एल० और ई० सी० एल द्वारा कहां-कहां और कितनी-कितनी जमीनें कोयलाधारक क्षेत्र अधिनियम और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत ली जा चुकी है या लिए जाने की संभावना है ; और

(ख) इन जमीनों के अधिग्रहण से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं ; और

(ग) क्या विस्थापित परिवारों की सहायतार्थ सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VTK-RAM MAHAJAN): (a) A statement is placed on the Table of the House.

(b) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) The acquisition of land under the Law requires payment of compensation to those whose lands are acquired and this responsibility is being discharged by the coal companies. However, in addition to cash compensation, the coal companies are also offering employment to the affected persons according to available vacancies. In the case of tribals whose lands are acquired, the companies have been advised also to provide homestead land to those tribals who have been displaced.

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Naresh Kushwaha.